POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अक्टूबर 2026 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राजस्थान में हुए निकाय चुनावों के परिणाम आ गए हैं। अब पंचायत चुनाव होने हैं। खबरें गांवों की चौपालों तक पहुंच चुकी है। गांव की सरकार बनाने के लिए मतदाता और राजनीतिक दलों में नए समीकरणों पर चर्चा होने लगी है।

विकास की असली नींव ग्राम पंचायत है। पंचायती राज चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि गांव के भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। इस बार नई मतदाता सूची, दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने और सरपंच चुनाव में शिक्षा की बाध्यता हटाने जैसी छूट ने चुनाव को आसान बना दिया है। राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,341 से बढ़कर अब 14,403 हो गई है। वहीं ग्रामीण वार्डों की संख्या 1,05,000 से बढ़कर 1,30,282 तक पहुंच गई हैं।

गांवों में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। 2020-21 के चुनावों में जहां मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 44 लाख के करीब थी, वह अब नई सूची के अनुसार 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार हो गई है। अर्थात 58 लाख से भी अधिक मतदाता बढ़े हैं। इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां इस बार चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा होगा, वहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ने की भी संभावना रहेगी।

इस बार चुनाव की बाजी युवा मतदाताओं पर निर्भर करती है। उन्हें ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनना होगा, जो राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए गांव की सरकार को मजबूत, प्रभावी, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार से मुक्त बना सकें।

उपभोक्ता आयोगों में मामले निपटाने में हो रही देरी-सुप्रीम कोर्ट



सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मामलों के निपटारे की गिरती दर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। सीजेआई सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी.मोहना की बेंच ने उपभोक्ता आयोगों के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला स्तर पर शिकायतों की प्रकृति और उनके गुण-दोष पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता। इसके चलते मामले राज्य आयोग होते हुए अंततः राष्ट्रीय आयोग में जमा होते जाते हैं और वहां पर लंबित मामलों का ढेर लग जाता है। सीजेआई ने कहा अगर यही स्थिति बनी रही तो आयोगों की संख्या बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा।

बेंच ने कहा, मामलों के निपटारे को यदि प्रोत्साहन से जोड़ा जाए, तो निपटारे की रफ्तार बढ़ सकती है। गौरतलब है कि उपभोक्ता आयोगों की निपटारे की दर 74% से घटकर 30% रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंडेंसी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट को लेकर कई आदेश दिए है। इनमें आयोगों की बेंचों को कहा गया है कि लंबित केस निपटाने का समय बताएं। साथ ही आयोग में लंबित मामलों की संख्या और उनकी संरचना का ब्योरा भी रिपोर्ट में दें। क्या आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाने की जरूरत है? रिपोर्ट में देश भर के सभी राज्य उपभोक्ता आयोग भी इसी तर्ज पर आंकड़ों को शामिल करें। साथ ही रिपोर्ट में सबसे पुराने लंबित मामले और वर्षवार मामलों की पेंडेंसी के रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया जाए।

बाइक के इंजन में आई खराबी, अब देना होगा हर्जाना



जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर में अभिषेक शर्मा ने अपने वकील के जरिए आयशर मोटर्स और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर केनिथ मोटर्स के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी अभिषेक शर्मा ने 2023 में केनिथ मोटर्स में रॉयल एनफिल्ड बाइक की सर्विस कराई थी। इसके बाद जयपुर से मनाली जाते समय बाइक के इंजन में खराबी आ गई। कुल्लू में जांच कराने पर सामने आया कि जयपुर में सर्विस के दौरान बाइक का ऑयल फिल्टर गलत लगाया गया। इससे नुकसान हुआ है। इसको लेकर परिवाद दायर कर बाइक में हुए नुकसान, मानसिक पीड़ा और अतिरिक्त खर्च की भरपाई की मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आयशर मोटर्स और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर केनिथ मोटर्स को सेवा में कमी का दोषी माना और आदेश दिया कि वे उपभोक्ता अभिषेक शर्मा को बाइक में हुए नुकसान, मानसिक पीड़ा और परिवाद खर्च की भरपाई स्वरूप 54,130 रुपए का हर्जाना अदा करें।

बच्चे छोड़ रहे 12वीं से पहले स्कूल

देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाओं के बीच, संसद की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में सरकारी स्कूली शिक्षा की बेहद कड़वी और चिंताजनक तस्वीर उभरकर सामने आई है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले हर 100 छात्रों में से केवल 27 बच्चे ही सीनियर सेकेंडरी तक पहुंच पा रहे हैं।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखने की चुनौती का समाधान नहीं किया गया तो सार्व-भौमिक शिक्षा का लक्ष्य आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएगा। रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 का हवाला देते हुए कहा गया है कि विभिन्न कारणों से स्कूलों में विद्यार्थियों के ड्रापआउट के कारण समस्या बढ़ सकती है।

कुपोषण की चपेट में आ रहा बचपन

पोषण टैकर द्वारा जुलाई 2026 के जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में 0 से 5 वर्ष तक के 6.69 करोड़ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।



इनमें से 11 प्रतिशत बच्चे अंडरवेट, 5 प्रतिशत ओवरवेट और 28 प्रतिशत बच्चों का शारीरिक विकास उम्र के हिसाब से मध्यम या गंभीर रूप से अवरुद्ध और 3 प्रतिशत बच्चे गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण की श्रेणी में पाए गए। बच्चों की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हर तीसरा बच्चा कुपोषण से जूझ रहा है। जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की स्थिति भी अच्छी नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए संचालित तमाम योजनाओं के तहत हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बच्चों के सेहत की यह तस्वीर काफी चिंताजनक है।

विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है।

दिया कुमारी ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र की अलसीसर से लेकर सीकर तक 14 प्रमुख क्षेत्रों की हवेलियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है। इससे क्षेत्र की 600 से ज्यादा हवेलियों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को की मूल्यांकन और नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन हवेलियों की दीवारों पर उकेरे गए जीवंत चित्र राजस्थान की ऐतिहासिक कला एवं सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की समृद्ध झलक को प्रस्तुत करते हैं और अनूठी भित्तिचित्र कला, स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक विरासत के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध हैं।

श्रमिकों का पैसा नहीं होगा हजम

कोटा जिले की सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत खेड़ली तवरान के मेहराना गांव में मनरेगा के तहत तलाब खुदाई व गहरीकरण कार्य में 60 श्रमिकों को करीब 1.33 लाख रुपए के भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है।

शिकायत पर जिला परिषद के लोकपाल ने जांच की तो तकनीकी और ब्लाक स्तर के अधिकारियों की ओर से नियमित निरीक्षण नहीं किया जाना भी सामने आया। लोकपाल ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली को गंभीर लापरवाही और उदासीनता माना है। उन्होंने खंडविकास अधिकारी एवं पदेन कार्यक्रम अधिकारी भानूमोली मौर्य के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने और 60 श्रमिकों को 1,33,320 रुपए ब्याज सहित दिलाने के निर्देश दिए हैं।

गांवों में बनेंगे अटल प्रगति पथ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजस्थान के प्रत्येक गांव को और आबादी क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ना है। इससे प्रदेश के गांवों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।

सरकार ने 5 हजार से अधिक आबादी वाले 28 जिलों के 192 गांवों में अटल प्रगति पथ बनाने के लिए 381.91 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। इन गांवों और आबादी क्षेत्रों में करीब 286 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन सड़कों के बनने के बाद ग्रामीण आबादी की मुख्य मार्गों, बाजारों, स्कूलों,अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। किसानों और व्यापारियों को अपनी उपज व सामान बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी।

मिड डे मीलः अधरझूल में बर्तन खरीद

राजस्थान के 53,738 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को खाना खिलाने के लिए बर्तन ही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने 595 करोड़ और प्रदेश सरकार ने 350 करोड़ कुल 955 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, लेकिन खरीद की प्रक्रिया पैसा ट्रांसफर करने के सिस्टम से अधरझूल में अटकी है।

शिक्षा विभाग स्कूलों को पैसा देकर बर्तन खरीदने की अनुमति नहीं दे रहा। जबकि केंद्र के अधिकारियों के सामने राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से देरी की वजह वित्त विभाग से समय पर राशि रिलीज नहीं होना बताया गया है। दोनों विभागों के अधिकारियों ने मामले को उलझा रखा है जिससे स्वीकृत राशि समय पर खर्च ही नहीं हो पा रही है।

ग्राम प्रतिहारियों का मानदेय प्रस्ताव

राज्य में राजस्व की अहम कड़ी माने जाने वाले ग्राम प्रतिहारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए राजस्व विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा जाएगा। फिलहाल इसे लेकर विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है।

जयपुर सहित प्रदेशभर में करीब 10500 ग्राम प्रतिहारी हैं। इन्हें सालाना एकमुश्त 15 हजार रुपए पारिश्रमिक दिया जा रहा है। प्रतिदिन के हिसाब से यह मानदेय करीब 42 रुपए बैठता है। राज्य में ग्राम प्रतिहारी पटवार मंडल से जुड़ी अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। ओलावृष्टि, गिरदावरी, मौका रिपोर्ट, आपदा सहित अन्य कामों में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ग्राम पतिहारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार से इस मामले में सकारात्मक कदम उठाने की गुजारिश की थी।

सिंचाई के लिए बनेंगे फार्म पौण्ड

किसानों को सिंचाई और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई फार्म पौण्ड योजना के तहत इस वर्ष 185 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 18 हजार फार्म पौण्ड बनाए जाएंगे। पूर्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस राशि की स्वीकृति दी थी।

कृषि विभाग के अनुसार पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 35 हजार 893 फार्म पौण्ड का निर्माण



कराया जा चुका है। इनके निर्माण के लिए किसानों को 328 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। योजना के तहत किसानों को फार्म पौण्ड निर्माण के लिए 63 हजार से लेकर 1 लाख 35 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इससे किसान खेत में बारिश के पानी को संग्रहित कर जरूरत के समय सिंचाई के लिए उपयोग में ले सकता है।

कीटनाशकों का उपयोग बन रहा घातक

दुनिया में करीब आधे किसान और कृषि श्रमिक हर साल जाने अनजाने कीटनाशकों के संपर्क में आने से गंभीर बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। यह पेस्टिसाइट एक्शन नेटवर्क द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया है।



कीटनाशकों के कारण होने वाली विषाक्तता से दुनिया में हर साल करीब 11 हजार लोगों की मौत होती है। इनमें से करीब 60 फीसदी मौतें भारत में होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनियाभर में करीब 38 लाख टन कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ, जो 1990 से दोगुना है। किसान और खेत मजदूर कई तरीकों से कीटनाशकों के संपर्क में आते हैं। सबसे ज्यादा जोखिम उस समय होता है, जब कीटनाशक तैयार करते हैं या खेतों में उनका छिड़काव करते हैं।

रात के अंधेरे में अनोखी जलक्रांति

बुजुर्गों के नेतृत्व में गुजरात के बाड़ोदरा के 10 गांवों में 3300 स्थानीय युवाओं ने जल संरक्षण के लिए आपस में मिलजुल कर ऐसा अनूठा काम कर दिखाया है जो सभी के लिए प्रेरणा दायक है।

इन गांवों के युवा दिन में नौकरी-खेती का और रात में खुदाई का काम कर अपने गांवों में 11 तालाब और 15 चेकडैम तैयार कर दिए हैं। साथ ही 533 वाटर टैंक का भी निर्माण किया है। इससे इन सभी गांवों का भूजल स्तर ऊपर आ गया है। इससे गांवों में पीने के पानी की समस्या दूर हो गई है। जमीन में उर्वरता बढ़ने से फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है साथ ही हरियाली होने से ग्रीन कवर भी बढ़ गया है।

बच्चों के बजट पर सरकारी कुंडली

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, दाखिले के बाद बच्चों को स्कूलों में रोकने के नाम पर चलाई जा रही करोड़ों रुपए की योजनाओं में भारी लापरवाही सामने आई है।

राज्य में 1 से 15 साल तक के बच्चों के लिए 37 योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी तरह कॉलेज छात्राओं और महिलाओं के लिए 9 बड़ी योजनाएं तो चलाई जा रही है, लेकिन सरकारी कारिंदों की बेरुखी के चलते इन योजनाओं में भी एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया।

धन्यवाद पत्र

मैं बनवारी लाल जाट निवासी बावड़ी तहसील, चौमूं जिला जयपुर ने अपने मकान के लिए जयपुर से हिंदवेयर कंपनी की शौचालय सीट खरीदी। सीट में कई स्थानों पर दरारें पाई गई, तो मैंने कंपनी में 3-4 बार शिकायत की। लेकिन कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने 'कट्स' द्वारा संचालित 'ग्राहक सहायता केंद्र' में शिकायत की। इसके बाद 'कट्स' की ओर से कंपनी को शिकायत पत्र लिखा गया। कंपनी ने तुरंत शौचालय सीट वापस लेने की सहमति दी। शिकायत के समाधान कराने के लिए मैं 'कट्स' के 'ग्राहक सहायता केंद्र' के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

यदि आप भी इसी प्रकार की कोई शिकायत का समाधान चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सहायता केंद्र

डी-217 भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

फोन: 0141-2282821, ई-मेल: cuts1@cuts.org

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर